देश-विदेश 39

अनियतकालीन बुलेटिन

नवम्बर-2021

सहयोग राशि तीस रुपये

इस अंक में विशेष

★ पण्डोरा पेपर्स : भ्रष्टाचार की बुनियाद है मजदूरों के श्रम की चोरी

★ फासीवाद का काला साया

★ बॉर्डर्स पर किसान और जवान

★ मखदूम मोहिउद्दीन : एक दहकती हुई आग

★ अफगानिस्तान : साम्राज्यवादी तबाही की मिसाल

देश–विदेश

अनियतकालीन बुलेटिन 39

अंक – 39

नवम्बर 2021

सहयोग राशि

तीस रुपये

सम्पादक

उमा रमण

उपसम्पादक

विक्रम प्रताप

सम्पर्क सूत्र

502/10 एस 1 साई कॉम्प्लैक्स,
डी ब्लॉक गली न. 1, अशोक नगर, शाहदरा
दिल्ली 110093

आवरण : गुरप्रीत भटिण्डा

Email: deshvidesh@rediffmail.com

फोन न. : 09818622601

www.deshvidesh.net

उमा रमण द्वारा प्रोग्रेसिव प्रिन्टर्स, ए- 21 झिलमिल इन्डस्ट्रियल एरिया, शाहदरा, दिल्ली-93 से मुद्रित और 502/10 एस 1 साई कॉम्प्लैक्स, डी ब्लॉक गली न. 1, अशोक नगर, शाहदरा दिल्ली-93 से प्रकाशित किया गया।

इस अंक में –

सम्पादकीय

पण्डोरा पेपर्स : पूँजीवादी भ्रष्टाचार की बुनियाद है मजदूरों के श्रम की चोरी 1

पण्डोरा पेपर्स	-राजेश कुमार	4
फासीवाद का काला साया	-प्रभात पटनायक	6
भारतीय राज्य और जन कल्याण!	-विशाल विवेक	10
जनसंख्या नियंत्रण विधेयक का तर्कहीन मसौदा	-वंदना प्रसाद, दीपा सिन्हा	13
भाजपाई कारकूनों ने किसानों को कार से रौंदा	-एस बी आजाद	15
बॉर्डर्स पर किसान और जवान	-भगवान स्वरूप कटियार	17

कहानी

पानीपत की चौथी लड़ाई	-सुबोध घोष	19

दिल्ली सरकार की 'स्कूल्स ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सलेंस' की योजना	-लोक शिक्षक मंच	25
'आप' की 'देशभक्ति की खुराक'	-सीमा श्रीवास्तव	28
मखदूम मोहिउद्दीन : एक दहकती हुई आग	-विजय गुप्त	30

समाचार-विचार

जाल-ए-दुनिया की बदहाली	38
बच्चों का बचपन छीन रहा है मोबाइल	40
क्यूबा तुम्हारे आगे घुटने नहीं टेकेगा, बाइडेन	41
खिलाड़ियों का इस्तेमाल 'फेस पॉउडर' की तरह	42
अय्यासी का अड्डा बनते हिमालयी इलाकों में तबाही	44
जर्जर स्वास्थ्य व्यवस्था, बे-मौत मरती जनता	45
बिना हिसाब लगाये और क्या हिसाब दें?	47
राजा महेन्द्र प्रताप के नाम पर हित साधती बीजेपी	49

लेखक संगठन आत्मालोचना से क्यों डरते हैं?	-शैलेन्द्र चौहान	51
पर्यावरण पर आईपीसीसी की ताजा रिपोर्ट	-अमरपाल	54
अफगानिस्तान युद्ध में अमरीका की हार	-विक्रम प्रताप	56
अफगानिस्तान : साम्राज्यवादी तबाही की मिसाल	-प्रवीण कुमार	59
एशिया में अफीम की खेती और साम्राज्यवादी नीतियाँ	-शैलेन्द्र चौहान	64
सऊदी अरब की साम्राज्यवादी विरासत	-यानिस इकबाल	66

सम्पादकीय

पण्डोरा पेपर्स : पूँजीवादी भ्रष्टाचार की बुनियाद है मजदूरों के श्रम की चोरी

काला धन और भ्रष्टाचार एक बेहद सनसनीखेज और लुभावना मुद्दा है। हमारे देश में अक्सर ऐसे मामले उजागर होते रहते हैं और भद्रजनों की सतही संवेदना और क्षणिक गुस्से को उकसाते रहते हैं। इसी सिलसिले की नयी कड़ी है पण्डोरा पेपर्स जिसमें हराम की कमाई से रातों-रात धनाढ्य बने देश-दुनिया के नामी-गिरामी हस्तियों के काले कारनामों का कच्चा चिट्ठा खोला गया है।

इण्टरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट्स (आईसीजेआई) द्वारा किये गये इस विराट भण्डाफोड़ में 117 देशों के 600 पत्रकार शामिल थे। इसे "अब तक का सबसे बड़ा पत्रकारिता सहकार" माना जा रहा है। पण्डोरा पेपर्स स्विट्जरलैंड, सिंगापुर, साइप्रस, समोआ, वियतनाम, हांगकांग में 14 अलग-अलग अपतटीय धन सेवा फर्मों के साथ-साथ बेलीज, सेशेल्स, बहामास और कुख्यात टैक्स हैवन ब्रिटिश वर्जिन आईलैण्ड्स में सक्रीय फर्मों के गोपनीय रिकॉर्ड से हुए लीक पर आधारित हैं। ये फर्म धनाढ्यों और निगमों के लिए ट्रस्ट और कम्पनी बनाते हैं तथा उनकी काली कमाई को बहुत कम या बिना टैक्स वाले देशों या इलाकों के बैंकों में गुप्त खाते खुलवाने में मदद करते हैं।

पण्डोरा पेपर इस गोरखधंधे में लगी कम्पनियों और उनके ग्राहकों के लीक हुए ईमेल, मेमो, टैक्स रिटर्न, बैंक स्टेटमेंट, पासपोर्ट स्कैन, कॉरपोरेट ढाँचे के नक्शे, गोपनीय ब्यौरे और रियल एस्टेट की गुप्त खरीद-फरोख्त के कागजात सहित लगभग 1.2 करोड़ फाइलों के आधार पर तैयार किया गया है। कुछ दस्तावेजों से पहली बार इन फर्जी मुखौटा कम्पनियों के असली मालिकों का खुलासा हुआ है। इसमें दुनिया भर के सैकड़ों शीर्ष नेताओं, अभिनेताओं, खिलाड़ियों और पूँजीपतियों के नाम हैं। अनुमान है कि इस सूची में 300 से अधिक भारतीय धनाढ्यों के नाम हैं जिनमें सचिन तेंदुलकर, अनिल अम्बानी, विनोद अडानी, जैकी श्रॉफ, किरण मजूमदार-शॉ, नीरा राडिया और सतीश शर्मा जैसी हस्तियाँ शामिल हैं।

लगभग पाँच साल पहले भी आईसीजेआई ने पनामा पेपर्स के जरिये ऐसे ही भ्रष्टाचार का खुलासा किया था, जो एक कानूनी फर्म, मोसैक फोन्सेका द्वारा लीक की गयी जानकारियों पर आधारित था। हमारे देश में इस भण्डाफोड़ पर काफी हो-हल्ला मचा था, क्योंकि इस सूची में भी काली कमाई में लिप्त कई नामी-गिरामी भारतीयों के नाम थे। लेकिन इन काली करतूतों में शामिल लोगों पर कोई कार्रवाई होना तो दूर, सरकार ने उनका नाम भी सार्वजनिक नहीं किया था। भ्रष्टाचार के प्रति लोगों के आक्रोश और अन्ना आन्दोलन का लाभ उठाकर ही मोदी सरकार और केजरीवाल सरकार सत्ता में आयी, लेकिन इन लोगों ने भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के बजाय इसे और भी बेलगाम छोड़ दिया।

दरअसल, भ्रष्टाचार इस व्यवस्था का अलिखित विधि-विधान और समानान्तर कार्य प्रणाली है। यह इस व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने में ग्रीस और मोबिल का काम करता है। लगभग दस-पन्द्रह साल पहले जानेमाने अर्थशास्त्री प्रोफेसर अरुण कुमार ने भारत में भ्रष्टाचार पर अपना अध्ययन प्रस्तुत किया था। उनका अनुमान था कि उस दौरान देश में 25,00,000 करोड़ की काले धन की समानान्तर अर्थव्यवस्था मौजूद थी। इस अपार काली कमाई के लिए जिम्मेदार कौन है? इस पर किसका कब्जा है?

प्रोफेसर अरुण कुमार का अनुमान था कि काले धन की अर्थव्यवस्था में देश की आबादी का 3 प्रतिशत ऊपरी तबका ही सबसे ज्यादा लिप्त है। इसमें पूँजीपति, उद्योगपति और उनका प्रबन्ध-तंत्र, बड़े डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर, कमीशन एजेंट, सट्टेबाज, तथा रियल एस्टेट, निर्माण उद्योग, मनोरंजन, शिक्षा, चिकित्सा, और सेवा क्षेत्र के विभिन्न व्यवसायों के मालिक, सरकारी अधिकारी, राजनीतिक पार्टियों के नेता और अन्य परजीवी शामिल हैं। इसी काले धन की बदौलत ये लोग देश के शासन-प्रशासन पर नियंत्रण रखते हैं, जिसके जरिये अपने लिए मोटी तनख्वाह और सुविधाएँ जुटाने के आलावा टैक्स में छूट, सरकारी धन का बन्दरबाँट, अरबों के फायदे के बदले करोड़ों की रिश्वत और सार्वजानिक सम्पत्ति की कानूनी-गैरकानूनी लूट में दिन-रात शामिल रहते हैं। यही तबका वैश्वीकरण, उदारीकरण और निजीकरण का सबसे बड़ा पैरोकार तथा नवउदारवादी लूटतंत्र का सामाजिक आधार है। इनको अपने अलावा सभी भ्रष्ट नजर आते हैं और भ्रष्टाचार पर सबसे ज्यादा प्रवचन भी ऐसे ही लोग देते हैं। अन्ना के आन्दोलन में भी इसी तबके के लोग सबसे आगे थे। सच तो यह है कि देश में पहले से ही जितने कानून मौजूद हैं, उनको कड़ाई से लागू कर दिया जाये, तो इस तबके के कुछ लोगों को छोड़कर बाकी सभी लोग सलाखों के पीछे होंगे। लेकिन इस व्यवस्था को चलानेवाले भी तो

यही लोग हैं, इसलिए हमारे यहाँ छोटे चोरों को सजा होती है, जबकि बड़े चोरों को सम्मानित किया जाता है।

मजेदार बात यह कि पूँजीवादी व्यवस्था में कोई भी भ्रष्टाचार अचानक शिष्टाचार बन जाता है, जब इस व्यवस्था को चलानेवाले लोग किसी भ्रष्ट आचरण-व्यवहार या पेशे को कानूनी जामा पहना देते हैं। काले धन को सफेद करने के लिए कानून बनाया जाना (मनी लांड्रिंग), सोने के आयात की छूट, सीमा शुल्क 350 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत किया जाना, श्रम कानूनों को बदल कर मजदूरों की निर्मम लूट को बढ़ावा देना, 1991 से पहले के गैरकानूनी काले धन्धों (काला बाजारी, जमाखोरी, सट्टेबाजी, टैक्स चोरी) को कानून बनाकर वैधानिक करार देना इसके चन्द उदहारण हैं। मोदी सरकार ने ऐसे कई कानून बनाये हैं और कई कानूनों पर अभी काम चल रहा है, ताकि भ्रष्टाचार को पवित्र बनाया जा सके। उदहारण के लिए-- 2019 में मोदी सरकार ने कार्पोरेट टैक्स 30 प्रतिशत से घटाकर 22 प्रतिशत कर दिया था, जिससे हर साल हजारों करोड़ का टैक्स बिना चुराये ही पूँजीपतियों की तिजोरी में चला जाता है। श्रम कानूनों में बदलाव और तीन खेती कानून भी मोदी सरकार द्वारा पूँजीवादी लूट और भ्रष्टाचार को कानूनी जामा पहनाने की दिशा में ही बढ़ाया गया कदम है, क्योंकि मजदूरों की छँटनी, तालाबन्दी तथा कृषि उपजों की जमाखोरी, कालाबाजारी और सट्टेबाजी, जो पहले गैरकानूनी और भ्रष्टाचार की श्रेणी में आते थे, अब कानूनी करार दे दिये जायेंगे।

यह सही है कि काला धन सफेद करने से सम्बन्धित भ्रष्टाचार की ये सनसनीखेज घटनाएँ देश, समाज और आम जनता के लिए बहुत ही खतरनाक हैं, और इन पर लगाम लग जाये तो जनता के लिए पहले से बेहतर शिक्षा, चिकित्सा, पीने के लिए साफ पानी, रहने लायक घर और जीने लायक जिन्दगी मिल सकती है और खुद पूँजीवाद की सेहत भी सुधर सकती है। 25,00,000 लाख करोड़ कोई छोटी रकम नहीं है। लेकिन यह रकम उस बुनियादी भ्रष्टाचार, उस "मूल पाप", उस लूट-खसोट के आगे कुछ भी नहीं है, जो पूँजीवाद की जीवन रेखा है, जो मजदूरों के श्रम की चोरी से कमाई जाती है। दिन-रात चलनेवाले इस भ्रष्टाचार को पूँजीपतियों का परम-पावन कर्तव्य मान लिया गया है, इसलिए इस पर कोई विवाद नहीं होता। कला धन और भ्रष्टाचार से होने वाली कमाई इस लूट के आगे ऊँट के मुँह में जीरा के बराबर भी नहीं।

भ्रष्टाचार का असली कारण 'मानव स्वभाव' या लोभ-लालच की आम प्रवृति नहीं हैं, जैसा कि पूँजीवादी पण्डित बताते हैं, बल्कि यह पूँजीवादी आर्थिक व्यवस्था के चरित्र में निहित है। इसका मूल स्रोत पूँजीपतियों द्वारा अतिरिक्त मूल्य की चोरी है, जिसे श्रमिक पैदा करते हैं।

पूँजीवादी समाज का विश्लेषण करते हुए कार्ल मार्क्स ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक "पूँजी" में इस सच्चाई को स्थापित किया है कि पूँजीवाद का अस्तित्व ही भ्रष्टाचार पर टिका हुआ है। मजदूरों के श्रम की चोरी करना, उस चुराये गये श्रम से अपने लिए निजी मुनाफा बटोरना और निजी सम्पत्ति जमा करना ही पूँजीवादी व्यवस्था की बुनियाद है। मुनाफे की यही हवस पूँजीपतियों को न केवल मजदूरों के साथ बल्कि पूरी दुनिया के साथ धोखाधड़ी करने तथा लूट-खसोट और भ्रष्टाचार के नये-नये तरीके ईजाद करके दौलत बटोरने के लिए उकसाती है। पूँजीवाद का एक ही उसूल है-- कानूनी या गैरकानूनी तरीकों से जितना ज्यादा और जितनी तेजी से मुनाफा कमा सकते हो, कमाओ!

पूँजीवादी समाज में मजदूरों का निर्मम शोषण इसलिए किया जाता है क्योंकि वे अपने श्रम से जितने माल का उत्पादन करते हैं, उसके कुल मूल्य से काफी कम कीमत पर उन्हें अपनी श्रम शक्ति पूँजीपतियों को बेचने के लिए मजबूर किया जाता है। उत्पादन के साधनों पर मालिकाना न होने के कारण ही मजदूरों के सामने अपनी श्रम शक्ति पूँजीपतियों को बेचने या फिर भूखा रहने के आलावा और कोई रास्ता नहीं होता है। मजदूर अपने श्रम का लाभ खुद नहीं ले पाते, क्योंकि पूँजीपति उनके श्रम का बड़ा भाग चुरा लेते हैं, और उसका इस्तेमाल उनके शोषण और अपने निजी मुनाफे के लिए करते हैं।

पूँजीवाद के अधीन मजदूरों की श्रम शक्ति को भी एक वस्तु, एक माल समझा जाता है, जैसे अनाज या कपड़ा या किसी दूसरी वस्तु की तरह। श्रम शक्ति की कीमत (या मजदूरी) भी किसी दूसरे माल की तरह उसके उत्पादन की लागत से, यानी सामाजिक रूप से आवश्यक श्रम की मात्रा से तय होती है। श्रम शक्ति के उत्पादन की लागत किसी मजदूर की श्रम शक्ति को बनाये रखने और उसके पुनरुत्पादन के लिए आवश्यक मूल्य या श्रम-लागत होती है। इसके लिए, पूँजीवाद में मजदूर को सिर्फ जीवन-यापन के लिए न्यूनतम जरूरतों को पूरा करने भर मजदूरी दी जाती है, उन्हें गुजारे भर की मजदूरी का भुगतान किया जाता है।

कार्य दिवस के दौरान मजदूर अपने खुद के पुनरुत्पादन के लिए आवश्यक मूल्य से कहीं अधिक मूल्य पैदा करता है। यानी, बारह घण्टे काम करने के बदले एक मजदूर को जितनी मजदूरी दी जाती है, वह उससे कहीं ज्यादा मूल्य पैदा करता है। काम के घण्टों के दौरान मजदूर जितने मूल्य का उत्पादन करता है और उसकी श्रम शक्ति को बनाये रखने और उसके पुनरुत्पादन के लिए पूँजीपति जितने मूल्य का भुगतान करता है, उसके बीच के अन्तर को अतिरिक्त मूल्य कहा जाता है।

इस बात को आसानी से समझने के लिए मजदूर के श्रम दिवस को दो भागों में बाँटा जाता है। पहले भाग के दौरान, मजदूर अपने लिए काम करता है, यानी उतनी वस्तुओं का उत्पादन कर

देता है जिसका मूल्य उसे मिलने वाली मजदूरी के मूल्य के बराबर होता है। दूसरे भाग के दौरान, मजदूर पूँजीपति के लिए काम करता है, यानी पूँजीपति के लिए अतिरिक्त मूल्य का उत्पादन करता है जिसके लिए उसे कोई मजदूरी नहीं मिलती है।

इस तरह मजदूरों द्वारा उत्पादित अतिरिक्त मूल्य को पूँजीपतियों द्वारा जबरन हड़प लेना ही पूँजीवादी शोषण है। पूँजीवाद में चूँकि मजदूर उत्पादन के साधनों का मालिक नहीं होता, इसलिए उसे मजबूर किया जाता है कि वह अपनी श्रम शक्ति पूँजीपतियों को कम से कम मजदूरी पर बेचे और उसके लिए अतिरिक्त मूल्य पैदा करे। यही अतिरिक्त मूल्य जो मजदूर पैदा करता है और जिसे पूँजीपति हड़प लेता है, पूँजीपति के मुनाफे का स्रोत होता है।

जाहिर है कि मुनाफे का बुनियादी स्रोत और पूँजीवादी उत्पादन की एकमात्र चालक शक्ति, मजदूरों द्वारा पूँजीपति के लिए किया गया मुफ्त श्रम है। इसलिए यह शोषण सबसे घिनौना भ्रष्टाचार है, चरम भ्रष्टाचार है और यही भ्रष्टाचार पूँजीवादी व्यवस्था की बुनियाद है।

मार्क्स ने कहा था कि "श्रम को हड़पे जाने का ही नतीजा है कि मजदूर, जिसके सामूहिक उत्पाद का हिस्सा लगातार पूँजीपति द्वारा जब्त किया जाता है, हमेशा अभाव में जीता है, जबकि पूँजीपति हमेशा लाभ में होता है। जो राजनीतिक अर्थशास्त्र, इस व्यवस्था को कायम रखता है और उसकी वकालत करता है, वह चोरी का सिद्धान्त है, सम्पत्ति के प्रति जो आदर भाव इस यथास्थिति को बनाये रखता है, वह जोर-जबरदस्ती का धर्म है।"

पूँजीवाद "निजी सम्पत्ति की पवित्रता" के सिद्धान्त पर आधारित है। लेकिन 'निजी सम्पत्ति' वास्तव में उस अतिरिक्त मूल्य के अलावा और कुछ नहीं है जो पूँजीपतियों द्वारा मेहनतकशों से, मजदूरों से चुरायी जाती है। निजी सम्पत्ति और कुछ नहीं बल्कि श्रमिकों से चुराया गया धन है। पूँजीवादी व्यवस्था में भ्रष्टाचार की असली जड़ यह सच्चाई है कि पूँजीवाद निजी सम्पत्ति की चोरी है, जो चरम भ्रष्टाचार है! काला धन और टैक्स चोरी तो इस लूट के माल को छिपाने और खपाने की धूर्ततापूर्ण चालें हैं।

हमें अपने आक्रोश का निशाना और अपनी कार्रवाइयों का लक्ष्य भ्रष्टाचार के इस बुनियादी स्रोत, पूँजीवादी व्यवस्था में दिन-रात होने वाले चरम शोषण, घृणास्पद भ्रष्टाचार पर केन्द्रित करना होगा जो हमारे देश-समाज की सभी असाध्य बीमारियों, बहुसंख्य मेहनतकश जनता के सभी दुःख-तकलीफों और कंगाली-बदहाली, चतुर्दिक सामाजिक पतन, मानव सभ्यता और प्रकृति की तबाही का असली कारण है। इसका एकमात्र विकल्प है-- न्याय-समता पर आधारित समाजवादी समाज का निर्माण, जो मुमकिन है, जरूरी है और लाजिमी है।

पाठकों से अपील

❑ 'देश-विदेश' अंक 39 आपके हाथ में है। हमारा प्रयास है कि इसे अनियतकालीन पत्रिका की जगह हर तीन माह पर नियमित प्रकाशित किया जाये।

❑ जिन साथियों को पत्रिका निरन्तर डाक से भेजी जा रही है, वे कृपया सूचित करें कि उन्हें पत्रिका मिल रही है या नहीं और उन्हें आगे से भेजी जाये या नहीं।

❑ देश-विदेश अव्यवसायिक पत्रिका है। यह साथियों के श्रम और सहयोग से ही प्रकाशित होती है। आर्थिक संकट से जूझते हुए अब तक हमने 39 अंक निकाले। पाठकों के सहयोग से ही यह सम्भव हो पाया।

❑ पत्रिका अभी भी अनियमित है, इसलिए नियमित चन्दे की दर तय करना सम्भव नहीं। डाक से मँगवाने के लिए 4 अंकों की सहयोग राशि 150 रुपये या आजीवन सदस्यता न्यूनतम 2000 रुपये निम्नलिखित बैंक खाते में अन्तरित करें और इसकी सूचना एसएमएस या ईमेल से भेज दें।

नाम : मोहित कुमार
मोबाइल नं. 8755762077
AC. No. : 30456084252
IFSC : SBIN0002292
स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया (एसबीआई),
एलम, शामली, उत्तर प्रदेश

मनी ऑर्डर भेजने का पता है-

अतुल कुमार गुप्ता
1/4649/45 बी, गली नं. 4,
न्यू मॉर्डन शाहदरा
दिल्ली- 110032

पण्डोरा पेपर्स

-- राजेश कुमार

पण्डोरा पेपर्स क्या हैं?

पण्डोरा पेपर्स में दुनियाभर के ऐसे लोगों का लेखा-जोखा है जिन्होंने अपने देश में टैक्स से बचने के लिए सम्पत्ति को अपनी पहचान छुपाकर टैक्स बचत का स्वर्ग कहे जाने वाले देशों में रखा। पहले भी 2016 में पनामा पेपर्स में इस तरह का खुलासा हो चुका है। उसके बाद 2017 में पैराडाइज पेपर्स में भी दुनियाभर के अमीरों द्वारा छुपायी गयी सम्पत्ति का ब्यौरा मिला था। पण्डोरा पेपर्स में दो सौ देशों के अमीरों का विवरण है। इसमें दुनियाभर से सैकड़ों राजनीतिज्ञ, फोर्ब्स पत्रिका की सूची में शामिल सौ से ज्यादा अरबपति, सेलिब्रिटीज, ड्रग माफिया, रॉयल फैमिली और धार्मिक गुरु लिप्त हैं। इतना ही नहीं, इसमें कई देशों के पूर्व राष्ट्रपति और मौजूदा राष्ट्रपतियों के भी नाम हैं। बड़े सरकारी अधिकारी, प्रधानमंत्री, जज, मेयर और सेनाध्यक्ष तक शामिल हैं। इस जालशाजी का खुलासा करने के लिए 117 देशों से, छः सौ से ज्यादा पत्रकार इस अभियान में शामिल रहे। "खोजी पत्रकार अन्तर्राष्ट्रीय संघ" ने एक करोड़ बीस लाख दस्तावेज इकट्ठा किये। ये दस्तावेज अंग्रेजी, स्पेनी, रूसी, फ्रांसीसी, अरबी और कोरियाई भाषा में हैं। दस्तावेजों की संख्या इतनी ज्यादा है कि अभी पण्डोरा पेपर्स का सम्पूर्ण विश्लेषण आने वाले वक्त में ही सम्भव हो पायेगा। लेकिन अब तक हुए खुलासे और रिपोर्टों के आधार पर इतना कहा जा सकता है कि दुनिया के अमीर इस धरती की सम्पदा को लूटने और अपनी तिजोरियाँ भरने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे।

कौन अपनी सम्पत्ति छुपाते हैं?

पूँजीपतियों में भी मुख्यतः दो चरित्र हैं-- पहला, वे जो पूँजी को विभिन्न उद्योगों में निवेश करते हैं और मुनाफा कमाते हैं। ये पूँजी को लेकर कुछ हद तक साहसी और निडर होते हैं। दूसरा, वे जिन्हें पूँजी के खोने का डर होता है। यह डर कई वजह से पैदा होता है जैसे सरकार के स्थायित्व पर भरोसा न हो या सम्पत्ति के लूट लिये जाने का खतरा हो आदि। इन्हें उसी सरकार पर भरोसा नहीं होता जिसमें यह खुद शामिल होते हैं, उसी व्यवस्था से डर लगता है जिसमें रहकर इन्होंने अकूत सम्पत्ति कमाई है। इस दूसरी केटेगरी में अधिकतर नेता, अभिनेता, सेलिब्रिटीज, धार्मिक गुरु और वित्तीय कारोबार करने वाले पूँजीपति होते हैं। इनके अन्दर परजीवीपन ज्यादा होता है। इसलिए ये अपनी पूँजी को अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में निवेश करने के बजाय एक हिस्सा कहीं सुरक्षित रखना चाहते हैं। इन्हें ऐसी जगहों की तलाश होती है जहाँ ये अपनी सम्पत्ति सुरक्षित रख सकें, इनकी पहचान भी न हो और टैक्स से भी बच जाएँ। इसी का परिणाम है कि यूनाइटेड किंगडम में डेढ़ हजार से ज्यादा सम्पत्तियाँ अवैध तरीके से खरीदी गयीं।

यह कैसे सम्भव है?

अपने देश से सुरक्षित तरीके से रुपये और सम्पत्ति को सीमा से बाहर निकालने के लिए ऑफशोर कम्पनियों के जाल बिछे हैं। ये कम्पनियाँ अपने ग्राहक के लिए विदेशों में सारे इन्तजाम करती हैं। उनके नाम-पते बदलना, पहचान गुप्त रखना जैसे कामों में विशेषज्ञ कम्पनियाँ सहयोग करती हैं। इन कम्पनियों के असली मालिकों की पहचान छुपा ली जाती है। कॉर्पोरेट टैक्स के लिए स्वर्ग कहे जाने वाले देशों में यह बहुत सामान्य है। कई देशों के कानून इतने लचीले हैं कि वे नयी कम्पनी खुलने पर ज्यादा जाँच पड़ताल नहीं करते और डायरेक्टर्स की पहचान को भी गुप्त रहते हैं। पूँजीपतियों के लिए इस धरती पर ऐसे स्वर्ग केमैन आइलैण्ड, ब्रिटिश वर्जिन आइलैण्ड, स्विट्जरलैण्ड और सिंगापुर हैं। पण्डोरा पेपर्स के खुलासे के बाद अमरीका में स्थित दक्षिणी डकोटा भी नये टैक्स स्वर्ग के रूप में उभर कर सामने आया है।

विदेशों में क्या वे सिर्फ रुपये छुपाते हैं?

नहीं। सिर्फ रुपया ही नहीं। इन सम्पत्तियों में बंगले, होटल, फार्महाउस और तरह-तरह के अय्याशी के साधन भी होते हैं। वे अपनी शेल कम्पनी खोलते हैं। शेल कम्पनी ऐसी हवाई कम्पनी होती है जिसका न कोई ऑफिस होता है न कोई कर्मचारी। धनी लोग ऐसी कम्पनी में बेशकीमती चीजें परिसम्पत्ति के रूप में रखते हैं। कम्पनी का बैंक खाता होता है। उसके डाइरेक्टर्स होते हैं। इसमें नगद रुपया से लेकर, कम्बोडिया से लूटी गयी प्राचीन मूर्तियाँ, पिकासो की पेंटिंग और ब्रिटिश कलाकार बैंग्सी के भित्ति

चित्र तक शामिल हैं।

अलग अलग राष्ट्रों का इन्हें लेकर क्या रुख है?

अभी ज्यादातर देश के शासक और मीडिया में पण्डोरा पेपर्स को लेकर चुप्पी साधे हुए हैं या घिसे-पिटे जवाब दे रहे हैं-- जैसे "जाँच होगी, दोषियों पर कार्रवाई होगी, अभी टिप्पणी नहीं कर सकते" आदि आदि। क्योंकि ज्यादातर देशों से या तो सरकार में शामिल लोगों के नाम पण्डोरा पेपर्स में हैं या उनके चहेते लोगों के।

खुद अमरीका के लिए पण्डोरा पेपर्स ने चुनौती खड़ी कर दी है। अमरीकी राष्ट्रपति ने दावा किया था कि वे वैश्विक वित्तीय व्यवस्था में पारदर्शिता लाने पर जोर देंगे। इन पेपर के लीक होने के बाद अमरीका खुद ही टैक्स से बचने के मामलों में स्वर्ग के रूप में सामने आया है। तमाम तरह के आर्थिक अपराधों में लिप्त सैकड़ों लोगों ने अमरीका के दक्षिणी डकोटा में अरबों डॉलर जमा किया है।

पण्डोरा पेपर्स की वजह से केन्या के राष्ट्रपति उहुरू केन्यट्टा के सामने धर्म संकट आ खड़ा हुआ है। उन्होंने खुद को भ्रष्टाचार के दुश्मन के रूप में पेश किया था। 2018 में बीबीसी को दिये एक इण्टरव्यू में उन्होंने जोर देकर कहा था कि "सभी सरकारी अधिकारियों को अपनी सम्पत्ति का ब्यौरा जनता के सामने सौंपकर पारदर्शिता लानी चाहिए।" अब खुलासा हुआ है कि इन्होंने अपने रिश्तेदारों के संग तीन करोड़ डॉलर विदेशों में जमा किये हैं। सवाल पूछने पर अभी इन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। यही हाल चेक गणराज्य के प्रमुख का है। पाकिस्तान में इमरान सरकार के एक महत्वपूर्ण मंत्री मूनिस इलाही ने सिंगापुर स्थित एक कम्पनी से 33 करोड़ डॉलर निवेश करने के लिए सम्पर्क किया।

एशिया, लातिन अमरीका, अफ्रीका, आस्ट्रेलिया, यूरोप, कोई भी पण्डोरा पेपर्स से बच नहीं पाया। ये बात भी ठीक है कि पण्डोरा पेपर्स में नाम आने भर से कोई अपराधी साबित नहीं हो जाता। हाँ, उसकी सम्पत्ति शक के दायरे में जरूर आती है। क्योंकि पूँजीवादी व्यवस्था सम्पत्ति की रक्षक होती है। उसे निजी सम्पत्ति से कोई एतराज नहीं। पूँजीवादी व्यवस्था में संविधान और कानून के हिसाब से सम्पत्ति के ऊपर टैक्स देना अनिवार्य है। दलाल किस्म के पूँजीपति इसी में हेराफेरी करते हैं। वे कानूनों का उल्लंघन करके या वकीलों की मदद से बारीकियों का फायदा उठाकर टैक्स से बचने में कामयाब हो जाते हैं। पण्डोरा पेपर्स में नाम आने पर भी ज्यादातर सेलिब्रिटीज, नेता और अफसरों ने किसी भी तरह की टिप्पणी से इनकार किया है। उनके वकील ही प्रवक्ता बने हुए हैं। वे कह रहे हैं कि हमारा क्लाइण्ट निर्दोष है, उसने फलाँ-फलाँ कानून के हिसाब से अपनी सम्पत्ति को विदेश में सुरक्षित किया है। भारत रत्न सचिन तेन्दुलकर का नाम पनामा पेपर्स में भी था और अब पण्डोरा पेपर्स में भी है। उनके वकील भी उन्हें बेकसूर बता रहे हैं।

पण्डोरा पेपर्स में भारत के तीन सौ से ज्यादा लोग शामिल हैं। जिनमें सचिन तेन्दुलकर, जैकी श्रॉफ, नीरा राडिया, अनिल अम्बानी, विनोद अडानी और सतीश शर्मा जैसे नाम प्रमुख हैं।

अनिल अम्बानी भारत में दिवालिया घोषित हैं और विदेश में 1.3 अरब डॉलर की कम्पनियाँ चला रहे हैं। यानी कि यहाँ उनकी कर्ज चुकाने की हैसियत नहीं और विदेशों में वे अरबों के मालिक हैं। इसीलिए देश में दिवालिया घोषित पूँजीपति विदेशों में जाकर अपने अड्डे जमाते हैं।

एक आम नागरिक इससे कैसे प्रभावित होता है?

देश में पैदा हुई पूँजी को चोरी छिपे देश से बाहर ले जाने के अर्थव्यवस्था पर बहुत व्यापक और गहरे प्रभाव पड़ते हैं। उदाहरण के लिए, पिछले दिनों लोगों ने अपनी बचत का पैसा भवन निर्माण कम्पनी ईरीओ (आईआरईओ) में निवेश किया। इस उम्मीद से कि एक दिन उन्हें अपना फ्लैट मिलेगा। एक्सोन कैपिटल और चिल्ड्रन्स फण्ड फाउण्डेशन जैसी संस्थाओं ने अरबों रुपये प्रोजेक्ट में झोंक दिये। फिर भी ईरीओ घाटे में रही। 2018-19 में इसका घाटा पाँच अरब रुपये था। लेकिन इसके मालिक ललित गोयल बीजेपी नेता सुधांशु मित्तल के साले हैं। मिस्टर गोयल ने पाँच अरब रुपये से ज्यादा की सम्पत्ति चार कम्पनियों के माध्यम से विदेशों में चोरी छिपे निवेश कर रखी है। इनका पसन्दीदा टैक्स हैवन है-- ब्रिटिश वर्जिन आइलैण्ड। पण्डोरा पेपर्स में मिले दस्तावेजों के हिसाब से इनका रिहाइशी पता है-- मैरिना बे रेसिडेन्सीज, 18 मैरिना, बुलेवार्ड, 45-08, सिंगापुर। इस तरह एक पूँजीपति की मुनाफे की सनक से कम्पनी दिवालिया घोषित हुई। एक तो लोगों की बचत डूब गयी, दूसरा, कोर्ट-कचहरी के चक्कर में लोगों का वक्त और पैसा बर्बाद हुआ, सो अलग। सरकार को टैक्स का चूना भी लगा। कम्पनी में काम कर रहे लोगों की नौकरी छूट गयी। कुल मिलाकर इसने व्यवस्था के संकट को और बढ़ा दिया।

अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार इस तरह की सम्पत्ति का अनुमान लगाया गया है। ऐसी अवैध सम्पत्ति 6 खरब डॉलर से लेकर 32 खरब डॉलर तक हो सकती है। इससे दुनियाभर की सरकारों को टैक्स में छह सौ अरब डॉलर का नुकसान होता है। अमरीका और चीन की जीडीपी मिलकर भी 32 खरब डॉलर नहीं हैं। इससे आप अन्दाजा लगा सकते हैं कि दुनियाभर के अमीरों